रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

रेलवे में सैलून

945. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय रेलवे के पास कुल कितने सैलून हैं और उनके रख-रखाव पर प्रति वर्ष कितनी धनराशि खर्च की जाती है; और

(ख) क्या सरकार सैलूनों को समाप्त करने का विचार रखती है, यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) 31-3-1987 को रेलवे पर उपलब्ध बोगियों और चौपहियों सहित रेल अधिकारियों द्वारा उपयोग किये गये निरीक्षण यानों/सैलूनों की कुल संख्या 506 ब. ला. और 272 मी. ला. है। इन निरीक्षण यानों की मरम्मत, अनुरक्षण और कर्षण पर हुए खर्च का अलग से हिसाब नहीं रखा जाता है क्योंकि वे समग्र कोचिंग बेड़ा, जो गणना की यनिट है, के भाग हैं।

(ख) जी नहीं। परिष्कृत प्रौद्योगिकी के बढ़ते हुए उपयोग, रेल परिसम्पत्तियों के इष्टतम उपयोग, संरक्षा की सर्वोपरि आवश्यकता और अधिकारियों द्वारा किये जाने वाले गहन स्थल निरीक्षणों, जो इन चल निरीक्षण यान सुविधाओं के बिना नहीं किये जा सकते हैं, में हमेशा हो रही वृद्धि को ध्यान में रखते हुए इन निरीक्षण यानों/सैलनों को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

Grants given to Voluntary Organisations in Madhya Pradesh

946. SHRI AJIT P. K. JOGI: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) what grant has been sanctioned to various voluntary organisations working in Madhya Pradesh for running non-formal education centres;

(b) whether any review of their working has been conducted;

(c) if so, the results thereof;

(d) what steps are being taken to improve their functioning; and

(e) what has been the contribution of these non-formal cetnres to the overall eradication of illiteracy in the State?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF EDUCATION AND CULTURE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI L. P. SHAHI): (a) Under the Scheme of Assistance to Voluntary Agencies for Non-formal Education for Elementary Age-group Children, Rs. 10,10,764/- has been released from 1983-84 to 1987-88 to voluntary agencies in Madhya Pradesh.

(b) to (e) National Institute of Educational Planning and Administration (NIEPA) made a study of 2 voluntary agencies regarding the growth of centres and utilisation of funds from 1980-81 to 1984-85. Their findings showed appreciable growth of primary NFE centres and increase in enrolment that indicated that voluntary agencies had taken interest in the programme. The voluntary agencies spent nearly double the amount of grant received by them.

The scheme of non-formal education has been revised in 1987, introducing simplified procedures.

Marketing of Substandard and Spurious Drugs

947. DR. (SHRIMATI) SAROJINI MAHISHI: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there is an increase in the marketing of substandard and spurious medicines and vaccines in the country;